

# फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 52

अक्टूबर 1992

50 पैसे

## थर्मल आन्दोलन

### एक मजदूर की निगाह में

[पिछले अंक में हमने थर्मल पावर हाउस में हो रहे एक सामान्य से वास्तविक मजदूर आन्दोलन की बहुत ही संक्षेप में चर्चा की थी। चौतरफा दबाव और संघर्ष व संगठन के पुराने तरीके कारगर नहीं — लगभग सौ साल से मजदूर इन हालात में रूबरू हैं। इन परिस्थितियों से पार पाने के लिये दुनिया-भर में मजदूरों ने विभिन्न प्रयास किये हैं, कर रहे हैं। इनकी जानकारी, इनका लेखा जोखा मजदूर पक्ष के विकास के लिये बहुत उपयोगी है। फैक्ट्रियों में होने वाले टकराव भी ऐसे प्रयासों का एक हिस्सा है। कई फैक्ट्रियों के घटना क्रमों पर निगाह डालने के बाद लगता है कि एक फैक्ट्री में मैनेजमेंट से आर-पार की लड़ाई के प्रयास की बजाय मैनेजमेंट के गले की ऐसी हड्डी बनना जो न निगली जा सके और न उगली जा सके, यह कारखानों में आज मजदूर पक्ष के लिये आवश्यक शक्ति-सचय के लिये एक उपयोगी तरीका है। फरीदाबाद में थर्मल पावर हाउस में हाल के एक बहुत ही सामान्य आन्दोलन से भी यही ध्वनि निकलती लगती है। इस विषय पर मजदूरों के बीच बहस-मुबाहिसे बहुत ही जरूरी है इसलिये यहां हम एक परमानेंट मजदूर की निगाह में थर्मल आन्दोलन प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की हालात में क्या करें और कैसे करें, इस बारे में अनुभव और विचार आमन्त्रित हैं।]

फरीदाबाद थर्मल पावर हाउस में १९७८ में मस्टर रोल, वर्क चार्ज परमानेंट के नाम से २५०० वरकर मैनेजमेंट के खाते में थे। आन्दोलन के बाद मस्टर रोल व वर्क चार्ज कैटेगरी वाले परमानेंट किये गये पर आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें थर्मल से ट्रान्सफर कर दिया गया। आज यहाँ १२०० परमानेंट और १२०० ठेकेदारों के वरकर काम करते हैं। परमानेंट वरकरों की ग्यारह यूनियनों व एसोसियेशन हैं।

इंजिनियरों का एसोसियेशन अलग से है।

पावर हाउस में परमानेंट कर्मचारियों को जनरेशन बोनस मिलता था जिसे इस साल फरवरी से मैनेजमेंट ने बन्द कर दिया। इस पर परमानेंट मजदूरों में हुई हलचल से ११ यूनियनों व एसोसियेशनों का जून के अन्त में जनरेशन बोनस बन्द करने के खिलाफ संयुक्त मंच बना। २८ जुलाई को संयुक्त मंच की पहली गेट मीटिंग हुई।

विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी कीर्तन/स्यापा का सिलसिला एक महीने चला। अगस्त के अन्त में अधिकारियों को नमस्ते करना, चाय व पानी ला कर पिलाना बन्द कर दिया गया।

मैनेजमेंट व नेताओं ने संयुक्त मंच को छिन्न-भिन्न करने के असफल प्रयास किये।

जनरेशन बोनस इंजिनियरों आदि को भी मिलता था इसलिये उसके बन्द किये जाने के खिलाफ उनमें भी रोष था। इंजिनियरों के एसोसियेशन की संयुक्त मंच में शामिल होने की बात सिरें नहीं चढ़ सकी। पानीपत थर्मल पावर हाउस वरकरों से सम्पर्क किया गया।

अक्टूबर के आरम्भ में आकस्मिक अवकाश ले कर अथवा अपने-अपने रैस्ट वाले दिन ३० से १६० तक कर्मचारी रोज धरने पर बैठे। यह सिलसिला दस दिन चला।

धरना कार्यक्रम के बाद २४ घंटे की क्रमिक भूखहड़ताल शुरू की गई। भूख हड़ताल पर भी कर्मचारी छुट्टी ले कर अथवा रैस्ट वाले दिन बैठते थे। आठ-दस वरकरों की भूख हड़ताल का यह सिलसिला सात दिन चला।

आन्दोलन का वर्क टू रूल चरण

शुरू होने ही वाला था कि २३ सितम्बर को मैनेजमेंट प्रतिनिधि से बातचीत में तय हुआ कि अक्टूबर में संयुक्त मंच से नेगोसियेशन करके हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड जनरेशन बोनस से जुड़े मसलों को निपटा देगा। इस पर संयुक्त मंच ने यह आन्दोलन स्थगित कर दिया है।

बीच में थर्मल वरकरों ने चीफ के घर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम कंसल किया तथा चन्डीगढ़ से किसी अफसर के आने की सूचना मिलते ही ढाई-तीन सौ वरकर इकट्ठे हो कर अफसर से सवाल-जवाब करने पहुँचे।

आन्दोलन के लिये चन्दा १० रुपये रखा गया था। नब्बे प्रतिशत कलेक्शन खुद कर्मचारियों ने अपने आप जमा किया। आन्दोलन में कोई कर्मचारी विकटीमाइज नहीं हुआ—कानूनी नुक्तों को ध्यान में रखने से इसमें बहुत मदद मिली।

इस प्रकार आन्दोलन का पहला चरण—जनरेशन बोनस बन्द करने के खिलाफ संयुक्त मंच का बनना, हाथ से लिखे इस्तेहार, गेट मीटिंग। दूसरा चरण—विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी। तीसरा चरण—कीर्तन/स्यापा। चौथा चरण—नमस्ते व चाय पानी बन्द। पाँचवाँ चरण—क्रमिक धरना। छठा चरण क्रमिक भूख हड़ताल। सातवाँ चरण — .....

फूट, परस्पर अविश्वास, डर, चमचागिरी के असर को कम करने वाले छोटे-छोटे कदम मजदूर पक्ष के निर्माण की तरफ उठे और रिजल्ट पोजीटिव रहा है।

**वेतन बढ़वाने के लिये ४ अक्टूबर से बंगलादेश में १५ हजार नर्सों ने हड़ताल शुरू कर दी है।**

## डेल्टन केबल्स

### रस्मी आन्दोलन का एक और उदाहरण

बरसों से जारी रूटीन दमन-शोषण में हाथ बँटाते आ रहे बिचौलिये/नेता कार में सवारी करने लगे ही थे कि डेल्टन केबल्स में लफड़ा हो गया। जनवरी ९१ में नई एग्रीमेंट लागू होनी थी पर मैनेजमेंट के लिये नई जरूरतें पंदा हो गई थी। दो सौ मजदूरों की छुट्टनी करना डेल्टन केबल्स मैनेजमेंट की आवश्यकता बनी। मैनेजमेंट की इस जरूरत को पूरा करने की कंपैसिटी डेल्टन के नेताजी की नहीं थी। इसलिये डेल्टन मैनेजमेंट ने पंगे लिये।

नई एग्रीमेंट पर खींचा-तान की आड़ में मैनेजमेंट ने छुट्टे चर रहे नेताओं को “काम नहीं, वेतन नहीं” की सूई चुभाई। दादाओं के बौखलाने पर मैनेजमेंट ने उन पर केस बना दिये। ले आफ-तालाबन्दी-हड़ताल की घालमेल में इस साल की पहली जून से डेल्टन केबल्स के मजदूर फैक्ट्री के बाहर कर दिये हैं।

रस्मी आन्दोलन कान खा रहे मजदूरों को पुकारने और साहब लोगों के साथ कुर्सी पर बैठने के लिये किये जाते हैं। छुट-पुट मामलों में यह कामयाब भी होते हैं लेकिन मैनेजमेंट और मजदूरों की महत्वपूर्ण मसलों पर खींचा-तान में यह नौटंकी साबित होते हैं। इस नौटंकी में आस लगाने की कीमत मजदूरों को चुकानी पड़ती है। पिछले चार महीनों के डेल्टन केबल्स घटनाक्रम पर एक नजर डालिये—

पहली जून से फैक्ट्री बन्द। मजदूरों को अब तक उनका मई माह का वेतन भी नहीं दिया गया है। लेबर डिपार्टमेंट के चक्करों का नतीजा रहा ६ जुलाई को दिल्ली में हरियाणा भवन में श्रम विभाग के साथ बैठक। उसके बाद “सिर्फ खानापूर्ति के लिये एक-दो बैठकें बुलाई गई हैं”। एक भूतपूर्व एम पी

और ट्रेड यूनियन नेताओं ने डेल्टन गेट पर गरमागरम भाषण दिये। डेल्टन केबल्स को खुलवाने के लिये सीटू के आह्वान पर “पहली सितम्बर को फरीदाबाद में सीटू से सम्बन्धित सभी यूनियनों ने हड़ताल की”—सीटू के गड़ कहे जाने वाले भलानी टूल्स (गेडोर) में मजदूरों को इस हड़ताल की जानकारी तक नहीं हुई। “इस हड़ताल का भी प्रशासन व सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा”। इस पर १८ सितम्बर से पाँच-पाँच मजदूर २४ घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे। यह सिलसिला २८ सितम्बर को खत्म कर दिया गया। फिर डेल्टन यूनियन के महासचिव जो कि जिला सीटू के सचिव तथा हरियाणा प्रदेश सीटू की बकिंग कमेटी के मेम्बर भी हैं, वे २८ सितम्बर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं—ओसवाल स्टील में आमरण अनशन ट्रेजडी थी, डेल्टन केबल्स में यह भूख हड़ताल कामेडी है।

यह अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि मजदूर और मैनेजमेंट दो पक्ष हैं। इन पक्षों में लगातार टकराव की वस्तुगत परिस्थितियाँ हैं। मजदूर पक्ष और मैनेजमेंट पक्ष के बीच मुद्दों पर फैसला ताकत से होता है। यहाँ दिखावे से बात नहीं बनती। दया-वया का यहाँ कोई बजन नहीं है। इसलिये मजदूरों के लिये सर्वोपरि महत्व के सवाल मजदूर पक्ष की ताकत बढ़ाने के कदम हैं। डेल्टन केबल्स के दुखद घटनाक्रम का भी यही सबक है कि रस्मी आन्दोलन के चक्कर में अपनी ताकत व समय गँवाने से बच कर ही मजदूर उपयुक्त कदम उठा सकते हैं।

यहाँ की फौजों के जासूसी विभाग के पूर्व जासूस मदनमोहन कहते हैं, “खुफिया ऐजेंसी के लिये काम करने से बेहतर है भीख माँगना।”

—इंडिया टुडे, १५ सितम्बर ९२

**हमारे लक्ष्य हैं:—** 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुंचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का काम में हाथ बटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद से मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिये बेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन भुग्गी, बाटाचोक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

## अमरीका

### कैंटरपिलर हड़ताल

कैंटरपिलर दुनिया में खेती तथा भारी काम की मशीनरी बनाने वाली प्रमुख कम्पनी है। अमरीका के अलावा बेल्जियम, फ्रान्स व जापान में भी कैंटरपिलर की फैक्ट्रियां हैं।

कैंटरपिलर की अमरीका स्थित फैक्ट्रियों में १९३८ के बाद से ग्यारह हड़तालों के जरिये मजदूरों ने कुछ सहुलियतें हासिल की थी जिन्हें हाल की हड़ताल के जरिये मैनेजमेंट ने खत्म-सा कर दिया है। बिचौलियों की अगुआई में हुये रस्मी आन्दोलन से मजदूरों को लगी चोट का एक और उदाहरण हाल का कैंटरपिलर घटनाक्रम है। अमरीका में और यहाँ बिचौलियों तथा उनके रस्मी-फर्जी आन्दोलन में क्वालिटी का फर्क नहीं है यह देखने के लिये अमरीका में छपने वाले दो छोटे अखबारों, दी पीपल और न्यूज एन्ड लैटर्स से प्राप्त सामग्री पर आइये एक निगाह डालें।

अमरीका में मजदूरों द्वारा प्राप्त सुविधाओं में कटौती, छँटनी और फैक्ट्रियाँ बन्द करने के सिल-सिले को दस साल से ज्यादा हो रहें हैं। इसके खिलाफ मजदूरों का असन्तोष आमतौर पर बिचौलियों की अगुआई में अभिव्यक्त हुआ है। बिचौलियों के कन्ट्रोल को बनाये रखने के लिये अमरीकी सरकार अपनी इमरजेंसी शक्तियों तक का इस्तेमाल करती रही है।

अमरीका में खेती तथा भारी काम की मशीनरी बनाने वाली अन्य कम्पनियों में हुई एग्रीमेंटों जैसी एग्रीमेंट करने से इनकार करके कैंटरपिलर मैनेजमेंट ने मजदूरों पर नवम्बर ६१ में हड़ताल थोप दी। पिछली एग्रीमेंट खत्म होने को आने के समय ओवरटाइम काम करवा कर यूनिन ने मैनेजमेंट के हाथ मजबूत किये थे। इसलिये नवम्बर ६१ में कैंटरपिलर की दो फैक्ट्रियों में हड़ताल करवाये जाते ही मैनेजमेंट ने कैंटरपिलर की दो अन्य फैक्ट्रियों में तालाबन्दी कर दी।

अपनी ताकत दिखाने के बाद मैनेजमेंट ने तालाबन्दी खत्म कर दी। तब उन फैक्ट्रियों के मजदूर भी हड़ताल में शामिल कर दिये गये। २१ फरवरी ६२ को एक और कैंटरपिलर फैक्ट्री के मजदूरों के हड़ताल में शामिल कर दिये जाने पर अमरीका में इस कम्पनी के हड़ताली मजदूरों की संख्या १२६०० हो गई। अमरीका में कैंटरपिलर की दो फैक्ट्रियों में यूनिन ने “हड़ताल नहीं” की एग्रीमेंट की हुई थी इसलिये यूनिन ने उन

फैक्ट्रियों के ३४०० मजदूर हड़ताल में शामिल नहीं किये। कैंटरपिलर की बेल्जियम-फ्रान्स-जापान स्थित फैक्ट्रियों में सामान्य प्रोडक्शन होता रहा।

इस हड़ताल के छठे महीने में प्रवेश पर पहली अप्रैल को मैनेज-मेंट ने नई भरती की धमकी दी। २० अप्रैल को बिना किसी एग्रीमेंट के यूनिन ने हड़ताल खत्म करने की अचानक घोषणा कर दी।

इस कैंटरपिलर घटनाक्रम में यूनिन को मजदूरों पर अविश्वास था, मजदूरों से यूनिन को डर लग रहा था। पिकेट लाइन पर ‘अनधिकृत’ विचार-विमर्श और पर्चे बांटने पर पाबन्दी के लिये यूनिन ने पुलिस का इस्तेमाल किया।

रस्मी आन्दोलन का नतीजा यह रहा है कि मजदूरों पर मैनेजमेंट ने अपनी शर्तें थोप दी हैं। मजदूरों की स्वास्थ्य सहुलियतों में तो मैनेजमेंट ने कटौती की ही है, सबसे बड़ा हमला मैनेजमेंट ने नये भरती होने वाले मजदूरों पर किया है। नये मजदूरों को इस समय मिल रही तनखा के आधे से भी कम पर काम शुरू करना होगा और बरसों बाद ही उनका वेतन अब मिल रही तनखा के आधे के बराबर होगा। पुराने मजदूरों को पुचकारने के लिये मैनेजमेंट ने छह साल तक छँटनी नहीं की चाशनी लगाई है। इस प्रकार कैंटरपिलर ने अमरीका में भारत जैसे वेतन देने की राह पर कदम बढ़ाये हैं।

वेतन वृद्धि के लिये आन्दोलन तो आज दुनिया में कहीं छुट-पुट ही हो रहे हैं जबकि वेतन कटौती के खिलाफ असन्तुष्ट विद्रोह व्यापक बनता जा रहा है। ऐसे में वेतन व्यवस्था के ही खिलाफ, वेज सिस्टम के खिलाफ आन्दोलन के मजदूर आन्दोलन की घुरी बनने की सम्भावना बढ़ रही है। आशा की किरण यही है।

### बिड़ला मिल ग्वालियर

जियाजी सूटिंग की शोहरत वाली जे सी मिल ग्वालियर के बिरलानगर क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख कपड़ा मिल है। सितम्बर के तीसरे सप्ताह में मैनेजमेंट द्वारा स्थानीय अखबारों में वेतन और छँटनी सम्बन्धी इशतहार छपवाने से जे सी मिल मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा। सरकार ने मजदूरों के खिलाफ ग्वालियर शहर में कर्फ्यू लगा दिया।

## पंजाब में मजदूर आन्दोलन

पंजाब में विजली बोर्ड और रोडवेज वरकरों के आन्दोलन तो चलते ही रहते हैं, फैक्ट्रियों में भी मजदूर चुप नहीं हैं। अबोहर में मवानी कपड़ा मिल के आन्दोलनरत मजदूरों पर पुलिस फायरिंग में तो छह मजदूर मारे गये थे। पंजाबी पत्रिका “इन्कलाबी जनतक लीह” से प्राप्त जानकारी के आधार पर पिछले अंक में हमने लुधियाना में कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन का जिक्र किया था। उसी पत्रिका के अक्टूबर अंक में लुधियाना में कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन के जारी रहने और जालन्धर जिले में मजदूरों की एक जीत के समाचार हैं।

जालन्धर जिले के बहिराम कस्बे में एक टोका फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में भी सरकारी कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। यहाँ के मजदूर एकजुट हुये और उन्होंने नंवा शहर स्थित लेबर डिपार्टमेंट को सरकारी कानून लागू करवाने के लिये एप्लिकेशन दी। अन्य स्थानों की ही तरह जालन्धर टुकड़खोर लेबर विभाग अधिकारियों ने सरकारी कानून लागू करवाने के लिये कार्रवाई करने की बजाय बड़े टुकड़े के लिये टोका फैक्ट्री मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी। इस पर मैनेजमेंट ने मजदूरों में फूट डालने, डराने फैक्ट्री बन्द करने की धमकी आदि हथकण्डे इस्तेमाल किये पर संगठित मजदूरों ने मैनेजमेंट की पार नहीं पड़ने दी। ई एम आई और प्रोविडेंट फण्ड लागू करने, हाजरी कार्ड, छुट्टियाँ तथा बोनस देने के साथ ही सात रुपये वेतन वृद्धि भी मैनेजमेंट को करनी पड़ी है।

१४ अगस्त को आरम्भ हुआ लुधियाना कपड़ा मजदूरों का आन्दोलन लटके-भटके भेलता हुआ सितम्बर में भी जारी रहा। लुधियाना रेंज के डी आई जी द्वारा मैनेजमेंटों के पक्ष में बयान के बाद से पुलिस रूपी संगठित गुन्डों और फुटकर गुन्डों ने मजदूरों पर हमले तेज कर दिये हैं। इन लोगों ने धरने पर बैठे हड़ताली मजदूरों पर हमला कर कई मजदूरों को गिरफ्तार किया और उस स्थल पर पुलिस की छत्रछाया में मैनेजमेंटों ने घरना शुरू कर दिया है।

लेकिन अन्य स्थानों की ही तरह लुधियाना के कपड़ा मजदूरों की राह में भी बिचौलिये काँटे बो रहे हैं। सीटू और हिन्द मजदूर किसान पंचायत एक तरफ दुगडुगी बजा रहे हैं तो एटक, बी एम एस और इन्टक दूसरी तरफ अपना राग अलाप रहे हैं। मैनेजमेंटों में अपने भाव बढ़ाने के लिये यह ट्रेड यूनिन

लीडर एक-दूसरे को पछाड़ने को अपना मुख्य काम बनाये हुये हैं। यह लोग अपनी सालाना फसल काटने की फिराक में हैं, कपड़ा मजदूरों की डिमान्डों से इनका कुछ लेना-देना नहीं है। कई सालों से चल रहे ऐसे डामों का ही नतीजा है कि लुधियाना के कपड़ा मजदूरों को हाजरी कार्ड तक नहीं दिया जाता। लगता है कि बार-बार लगी ठोकरी से इन मजदूरों ने कुछ सीखा है और इसकी भुलक बिचौलियों के प्रति उनके रूख में झुकने लगी है।

एक बढ़िया समाचार यह है कि लुधियाना के मोल्डरों और स्टील वरकरों ने कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन में अपनी शिरकत बढ़ाई है।

### शक्तिशाली

सात का समूह, यानि अमरीका-जापान-जर्मनी-फ्रान्स-कनाडा-इटली-इंग्लैंड की सरकारों की गिरोहबन्दी। यह सरकारें आपस में रेगुलर मीटिंग करती हैं। छोना-झपटी में अपना-अपना हिस्सा बढ़ाने के लिये जाल बुनती हैं। और इस साल सितम्बर में इन सरकारों के वित्त मंत्रियों की वाशिंगटन में मीटिंग को अमरीका के जाने-माने अखबार न्यूयार्क टाइम्स ने पीड़ित व्यक्तियों की मीटिंग बताया। वजह? इस वक्त इन वलवानों में किसी की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बजट घाटे, ऊँची व्याज दर और मंडी की समस्याएँ विकट हो गई हैं। ब्रिटेन में मंदी का दौर, जर्मनी सरकार उधार ले कर काम चला रही हैं, फ्रान्स में बेरोजगारी की समस्या विकट, इटली सरकार भारी बजट घाटे की भरपाई नहीं कर पा रही, अमरीका व कनाडा में मंदी तथा बेरोजगारी की समस्याएँ उग्र, जापान में स्टाक बाजार में ५०% से अधिक कारोबार ठप्प हो चुका है .....

ऐसे में तब से राहत के लिये चूल्हे में कूदने वाले कदमों की भरमार: अमरीका सरकार पहली अक्टूबर से शुरू हुये वित्त वर्ष में फीजों पर ही ८२ खरब २० अरब रुपये खर्च करेगी .....

मौजूदा समाज व्यवस्था की घुरी बना सात का गिरोह शक्तिशाली है क्या?

### डर...

बड़ी कम्पनियों द्वारा कई देशों में फैक्ट्रियाँ लगाना आम बात हो रही है। फोर्ड मोटर कम्पनी ने भी कई देशों में फैक्ट्रियाँ लगा रखी है। मैक्सिको में भी फोर्ड फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के मजदूरों ने आन्दोलन के दौरान फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फोर्ड मैनेजमेंट, मैक्सिको सरकार और सरकारी यूनिन ने हथियारबन्द गुन्डों को फैक्ट्री में भेज कर मजदूरों पर गोलियाँ चलवाई। और...

**और फोर्ड मैनेजमेंट ने सर्वोपरि माँग यह की कि मैक्सिको में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूर अमरीका और कनाडा में फोर्ड फैक्ट्रियों के मजदूरों के साथ सब सम्बन्ध खत्म करें!**

है ना समझने की बात?

[सामग्री हमने “न्यूज एन्ड लैटर्स” पत्रिका के मई १९६२ अंक से ली हैं।]

### ओरियन्ट फैन

काफी समय से किसी बिचौलिये के साथे से ओरियन्ट फैन के मजदूर मुक्त थे पर बिचौलिया संस्कृति से नहीं। “कोई कर दे” की सोच ओरियन्ट फैन के मजदूरों में भी जड़ जमाये है। इसलिये मैनेजमेंट के हमले के जवाब में अपनी ताकत बढ़ाने के लिये कदम उठाने की बजाय यह मजदूर इधर-उधर ताकने लगे, इस-उस बिचौलिये के पास भाग-दौड़ करने लगे। इस सबका नतीजा यह है कि पहली सितम्बर से ओरियन्ट फैन के मजदूर दस-बीस के झुन्ड में फैक्ट्री गेट पर मक्खियाँ मार रहे हैं। अपनी और अपने विरोधी की ताकत में फर्क करके ही ओरियन्ट फैन के मजदूर इस दलदल से निकल सकेंगे।

